

was a year and a half before. The number of persons out of work and the number of mills closed is much less than before; about half as compared to what it was a year and half before.

Shri S. M. Banerjee: I want to know whether all the good replies are meant for the Minister and not for the Deputy Minister.

Some Hon. Members rose—

Mr. Speaker: Next question. I have allowed a number of questions. It has become a contagion; if I allow one hon. Member after I had called another question, every other hon. Member wants to take advantage of it.

पुराने किले से विस्थापितों का हटाया

ज्ञाना

+

- *६२०. { श्री प्रकाश बीर शास्त्री :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री रामजी वर्मा :
श्री प्र० चं० बरधवा :

क्या पुनर्वासि तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पुराने किले में रहने वाले विस्थापितों को ३० नवम्बर, १९५९ तक उसे खाली करने का नोटिस दे दिया गया है ; और

(ख) उन में से कितने विस्थापित व्यक्ति लाजपत नगर में प्लाट मिल जाने पर वहां से चले गये हैं ?

पुनर्वासि उपमंत्री (श्री पू० शं० नासकर) :

(क) जी हाँ।

(ख) ३ परिवार।

श्री प्रकाश बीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूँ कि कुल कितने परिवार वहां रहते हैं और वे अभी तक वहां से क्यों और किस तरह नहीं हटना चाहते हैं ?

पुनर्वासि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री- (श्री मेहर चन्द खन्ना) : परिवारों की तादाद मेर स्याल मे चार पांच सौ के करीब है और चार वर्ष से — १९५५ से ले कर १९५९ तक — यह सवाल इस पालियामेंट के सामने आ चुका है। इस बारे में काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन नज़र यह आता है कि वे हमारी कोई बात मानने के लिए या सोचने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री प्रकाश बीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसे कौन से कारण उन्होंने उपस्थित किए हैं कि जिस से सरकार जो स्थान उन को देना चाहती है, वहां वे परिवार नहीं जाना चाहते हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : हमारे और उन में जो मत-भेद है, वह सिर्फ यह है कि जो चीज़ वे चाहते हैं, वह हम दे नहीं सकते और जो मैं दे सकता हूँ उस को लेने के लिए वे तैयार नहीं हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री जी ने अभी फ़रमाया कि जो चीज़ वे चाहते हैं, उस को वह दे नहीं सकते और जो वह दे सकते हैं, उन को वे परिवार लेना नहीं चाहते। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यहां आखिर कोई बीच वाला रास्ता नहीं निकाला जायगा।

श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय सदस्य के यहां आने से पहले भी इस बारे में कोशिश की गई और उन के आने के बाद भी दो बरस तक कोशिश की गई।

Shri S. M. Banerjee: I take exception to this, Sir, I have not been elected at his mercy. What is this. He is saying:

"माननीय सदस्य के आने से पहले . . ."

Shri Mehr Chand Khanna: Let me reply, Sir, in English.

Mr. Speaker: I have understood what the hon. Minister has said. The hon. Minister need not say, after the Member has come in it has not been found possible.....

Shri P. S. Naskar: He did not say that.

Shri Mehr Chand Khanna: What I said was, two years before the hon. Member came to this House and two years after the hon. Member came to this House, I have made repeated efforts in this direction.

Shri S. M. Banerjee: You have not fought the elections. You have come to the Rajya Sabha. That is the difference.

Some Hon. Members: That was a humorous remark.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आनरेबल मिनिस्टर साहब ने इस हाउस में बड़ी मेहरबानी कर के एक आफ़र दी थी कि एक-एक प्लाट और पांच-पांच सौ रुपये हर एक को दिए जाएंगे। मैं यह दर्शाहूँ करना चाहता हूँ कि क्या वह आफ़र खुली है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : नहीं, मेरे नोटिस के बाद वह आफ़र माफूँ हो चुकी है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उस आफ़र को किसी तरह से ठिक लिया जा सकता है, जब कि वह उन का हक है बमुज़ब उन कवायद के जो बुद मिनिस्ट्र. ने बनाए हैं, और क्या यह मुमकिन है कि उस आफ़र ने कुछ थोड़ी सी इतनी ज्यादाती कर दी जाय कि उन के लिए उन प्लाट्स पर मकान बना कर दे दिए जायें ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहाँ तक आफ़र का ताल्लुक है, वह तीन बरस श्रोन रही। अब मेरा दुकान का सौदा सब बिक चुका है।

I may say in English that I have reached more or less the bankruptcy stage. अब मेरे पास काई जमान नहीं रह गई है। आज से दो चार छः महीन पेशवर

लाजपत नगर मेरे पास था चाकर करने के लिए, लेकिन आज लाजपत नगर में भी मामला खत्म ही गया है। इस वास्ते मैं दूँ जो कहां से दूँ ?

श्री हलबीत सिंह : माननीय मंत्री जी ने अभी फरमाया कि जो वे लोग चाहते हैं, उसे वह दे नहीं सकते हैं और जो वह देना चाहते हैं, उसे वे लोग लेना नहीं चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वे क्या क्या चीजें हैं जो वे चाहते हैं और वे क्या क्या चीजें हैं जो मिनिस्टर साहब देना चाहते हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जो वे चाहते हैं वह ऐसी जमीन है जहां कि मिलिटरी इंस्टालेशंस मौजूद हैं और वे हट नहीं सकते हैं। मैं उनको लाजपत नगर में जमीन देना चाहता था जो कि दिल्ली में मेरे पास एक बेहतरीन कालोनी है, जहां स्कूल है, अस्पताल है, कालेज है, गर्ल कालेज है, एक लाल के करीब आबादी है और वहाँ धारणार्थी बसते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि उनकी मिनिस्ट्री का दिवाला निकल चुका। लेकिन मैं अर्थ करना चाहता हूँ कि जहाँ तक उन लोगों का सवाल है, उनका रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है और हमारी गवर्नमेंट का दिवाला नहीं निकला है। इस लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मिनिस्टर साहब मेहरबानी कर के ऐसे आदमियों को, जो कि कई वर्षों से आपके डिम्बे पड़े हुए हैं, एक बार फिर आफ़र देगे और उनको फिर बसाने की कोशिश करेंगे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : अर्थ वह है कि अगर मैं निविदा को जारी रखता हूँ तो कहा जाता है कि बिपटा रहता है मिनिस्ट्री को खत्म नहीं करना चाहता। अगर मिनिस्ट्री का काम खत्म करना चाहता हूँ तो कहा जाता है कि वे लोग रह गए हैं। मैं सिर्फ इतना अर्थ करना चाहता हूँ कि वह मिनिस्ट्री या वह गवर्नमेंट जो कि दिल्ली में ४०-५० हजार

यूनिट्स बनाती है, २०-२५ करोड़ रुपये की इमारतें खड़ी करती है, क्या चार पांच सौ भाइयों का काम नहीं करना चाहती ? मेरी तकलीफ यह है कि वे मेरे बताये हुए रास्ते पर चलना नहीं चाहते, मेरे भाई, मुनना नहीं चाहते । ऐसी हालत में मैं करूँ तो क्या करूँ

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं बतलाना चाहता हूँ कि दरअसल में वे सब के सब इस बात के स्वादिष्टमन्द् हैं कि उनको बसा दिया जाए । आनरेबल मिनिस्टर साहब के कहने के मुताबिक अगव वे बाहर भी निकल जाएँ और अगर उनको कोई जगह भी दी जाएँ जो कि लेना चाहते हैं, तो ऐसी हालत में क्या मिनिस्टर साहब फिर बारा इस हाउस की दरखास्त पर कोशिश करेंगे कि उनको बसा दिया जाए ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने स्पीकर साहब के हुक्म के मुताबिक लास्ट टाइम यह माना था कि छः महीने की इजाजत दी जाए । मैं आज कोई नई एश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं हूँ बल्कि असल में तकलीफ यह है कि अगर मुने यकीन हो कि मेरी बात सुनने के बाद वे लोग वहाँ चले जाएँगे तो मैं कुछ कहूँ । इस काम में चार बरस तो गुजर चुके हैं । आखिर मेरी जिम्मेवारी है इस काम को करने की और मैं ज्यादा एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर आनरेबल स्पीकर साहब से एश्योरेंस दिलवा दी जाए तो फिर क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब उबलो बसाने की कोशिश करेंगे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जब तक मैं रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर हूँ, रिफ्यूजीज को बसाना तो मेरा काम ही है ।

Shri S. M. Banerjee: Only one question, Sir, about the land.

Mr. Speaker: The hon. Minister has stated I have also interested myself.

Shri S. M. Banerjee: The hon. Minister has stated that the land which they wanted belonged to the Defence Ministry. My information is that the land has been taken over by the Housing Ministry. So, the land does not remain in the hands of the Defence Ministry. Now the land can be allotted to them. I want a categorical answer to this.

Mr. Speaker: It is not the Housing Ministry, it is the Rehabilitation Ministry here.

Shri S. M. Banerjee: No question of Defence.

Mr. Speaker: The hon. Members must persuade those people also.

Shri S. M. Banerjee: We are doing.

Mr. Speaker: They go round to everyone, and ultimately come to the Speaker also.

Shri S. M. Banerjee: They come to you also.

Shrimati Renu Chakravartty: The hon. Minister must reply to this

Mr. Speaker: It is in the hands of the other Ministry. This Ministry is not able to do anything.

Shrimati Renu Chakravartty: He had said it could not be given because it was in the hands of the Defence Ministry and they want it for urgent public purposes, but it is in the hands of the Housing Ministry.

Mr. Speaker: If it is not in the hands of the Defence Ministry which may have overriding considerations to keep it, if they do not think it necessary to keep it for themselves and have handed it over to another civil Ministry, the Housing Ministry, why not the Rehabilitation Ministry take it over themselves again?

Shri Mehr Chand Khanna: The Minister of Works is sitting here, his Deputy is also sitting here. I can only

offer what I have in my possession. I was prepared to offer land in Lajpat Nagar, I have no land left there. The only possible colony I can think of is Kalkaji, but I am making no offer.

Mr. Speaker: All that the hon. Members suggest is that as between these two Ministries, why not they decide this matter and hand it over to them.

Shri Braj Raj Singh: What are the reactions of the Housing Minister?

Mr. Speaker: The hon. Minister also may say something. How long is this trouble to be kept on? If it is possible, why not arrange between the two Ministries?

Shri Mehr Chand Khanna: You would remember, Sir, that last time when the question of this land came up, the Prime Minister was here, and he very categorically stated that the land which is required for defence purposes, where we may have our own military installations, cannot be given. I believe they have got wireless masts all over that area. It is required for defence purposes. But what I beg to submit, and what I want to tell the House through you, is only one thing. I see nothing wrong with Kalkaji, I see nothing wrong with Malaviya Nagar, I see nothing wrong with Lajpat Nagar. Why not all my friends who try and persuade me persuade these gentlemen? If a lakh of people can live in Lajpat Nagar, 40 to 50 thousand can live in Kalkaji and Malavya Nagar, what is wrong that these friends cannot go there?

Shri S. M. Banerjee: Let a committee be appointed.

Pandit Thakur Das Bhargava: As a matter of fact, they are prepared to go there. Previously the hon. Minister offered them; then he said he would give them in another place. So, under this idea they were thinking that they would get some other place. Now they are quite ready to go to any place which the Govern-

ment offers to them. The responsibility of both the Ministries is the same. I would request both the Ministers to kindly come to their help and see that these people are rehabilitated and not thrown on the streets.

Mr. Mehr Chand Khanna: The question of the other Ministry does not arise. As far as these friends of mine are concerned, I offered them lands, I offered them built-up accommodation, I offered them cheap tenements. They wanted 100 sq. yards, I gave them 100 sq. yards each. Then it was represented to me that the families which have more than five members should be given 200 sq. yards. I agreed even to that. I even told them I was prepared to give them the benefits of the compensation scheme. If in spite of all the concessions that have been offered, they are not willing to come to any terms, a historical monument of the importance of Purana Quila cannot be allowed to become the property of the displaced persons, they have to go. Let me make a policy statement, you may accept my decision or not, but I cannot allow the Purana Quila which is a historical monument, regarding which there is constant pressure upon this Ministry to be in their possession; it shall have to be vacated.

Pandit Thakur Das Bhargava: There is no question of

Mr. Speaker: I am not going to allow a discussion of this matter

Pandit Thakur Das Bhargava: I am not discussing.

Mr. Speaker: I have allowed sufficient number of questions.

Pandit Thakur Das Bhargava: I only beg the Minister to come to their help and rehabilitate them. They are prepared to vacate.

Mr. Speaker: Shri D. C. Sharma:

Shri D. C. Sharma: Did a deputation of the residents of Purana Quila meet the hon. Minister?

Mr. Speaker: No, no. - am not allowing it. I asked him to put the next question.

All the same, I would appeal to the Rehabilitation Minister. If the property has been given away by the Defence Ministry to the Housing Ministry, why not the Rehabilitation Ministry take it up?

Shri Mehr Chand Khanna: There is some kind of misunderstanding. I got this land in Purana Quila, I believe from the Ministry of Education in olden times. There was a camp and we gave them temporary accommodation. Now, as far as I am personally concerned, I had land in Lajpat Nagar. If there is any other land belonging to the Defence or the Housing Ministry, that is not my concern.

Mr. Speaker: I am only appealing to the hon. Minister: He need not take it up by himself. Why not the Rehabilitation and the Housing Ministry settle it, if the Defence Ministry does not want it? That is what exactly has been said. I leave it to both the Ministries.

Shri C. K. Bhattacharya: We might have a half-hour discussion in which the three Ministries should take part.

Mr. Speaker: I would only appeal to all the three Ministries, because it is coming up again and again, the Defence, Rehabilitation and Housing Ministries, to sit together. If the Defence Ministry does not want it, let there be no kind of prestige in this matter. Let the matter be settled; once again the Housing Ministry may give it to the Rehabilitation Ministry.

The Minister of Defence (Shri Krishna Menon): This question is not addressed to me, but since I am present I may say I have no knowledge of our saying we want it or we do not want it.

Mr. Speaker: Very well, he might consider it.

Shri Mehr Chand Khanna: May I submit one thing for the information

of the House, that before these notices were issued, this matter was before the Cabinet where all the Ministries were represented, and it is on the decision of the Cabinet that action was taken.

Pandit Thakur Das Bhargava: These people even went to the hon. Prime Minister; and they asked Government to give them houses. Fifty houses were offered, but they were not subsequently given.

Mr. Speaker: Next question.

Indians Kidnapped by Pakistanis

+
*621. { Shri D. C. Sharma:
Shri Pangarkar:

Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) the number of Indian nationals kidnapped so far by Pakistanis from the Indian side of the West Bengal-East Pakistan border since August, 1959;

(b) the number of Indians out of them released so far; and

(c) the action taken for getting the release of the rest of them?

The Parliamentary Secretary to the Minister of External Affairs (Shri J. N. Hazarika): (a) and (b). 8 (eight) out of which 4 (four) have been released.

(c) Both the State and Central Governments are actively pursuing the question of release of the remaining Indian nationals with the Government of East Pakistan in accordance with the agreed decisions taken at the last Chief Secretaries' Conference held at Calcutta and the Minister-level Conference on "Indo-East Pakistan Border Problems" held at Delhi and Dacca.

Shri D. C. Sharma: May I know whether there has been an increase or decrease in the number of persons kidnapped, as compared with that during the corresponding period in 1958?